खंड 20 नंबर 2 अप्रैल 2024

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

आरआईएस डायरी
-अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

समुद्री परिदृश्यः अतीत, वर्तमान और भविष्य

सीएमईसी विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला

(बाएं से) प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी; श्री राजीव जलोटा; डॉ विश्वपति त्रिवेदी; और श्री सुभोमोय भट्टाचार्जी

आरआईएस ने 29 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया। इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव जलोटा ने दिया। सीएमईसी विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य इस उद्योग की अग्रणी हस्तियों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करते हुए समुद्री व्यापार और शिपिंग के क्षेत्र में ज्ञान और विमर्श को बढ़ावा देना है।

समुद्री व्यापार नीति के क्षेत्र के दिग्गज होने के साथ ही साथ भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक के अध्यक्ष होने के नाते व्यापक अनुभव रखने वाले श्री जलोटा ने "समुद्री परिदृश्य का चित्रण : अतीत, वर्तमान और भविष्य" विषय पर बेहद विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया।

उन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र के विस्तृत होते आकार पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा, "अनेक मेगा पोर्ट क्लस्टरों और वैश्विक आर्थिक गलियारों की योजना के साथ भारत एक महत्वाकांक्षी गंतव्य की ओर कदम बढ़ा चुका है और इस बात पर गौर करना बेहद सुखद है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं।" उन्होंने समुद्री क्षेत्र की सहस्राब्दियों से चली आ रही अतीत की परंपराओं, जहां भारत ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी का संक्षिप्त विवरण पेश करते हुए उनको मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 में इस क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए वर्तमान और भविष्य के नीतिगत परिप्रेक्ष्यों से जोड़ा। उन्होंने बताया कि इन दोनों का उद्देश्य आने वाले दशकों में समुद्री क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की व्यापक रूप से विस्तारित व्यापार क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्थापित करना है।

श्री जलोटा ने श्रोताओं को विचाराधीन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना का उल्लेख किया, जिसमें त्वरित विकास के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल होगा। उनके अनुसार, इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहल निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया खाड़ी को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की योजना रही। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बंदरगाह के बुनियादी ढांचे ने वैश्विक मानकों के मुकाबले अपने प्रदर्शन संकेतकों में तेजी से प्रगति की है और अब बंदरगाह सीमा से परे लंगर डालने वाले जहाजों से राजस्व हासिल करने जैसी नई व्यावसायिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने बताया

शेष पृष्ठ 16 पर जारी...

बंगाल की खाड़ी और भारत–जापान आर्थिक संबंध

(बाएं से) प्रोफेसर राधारमण चक्रवर्ती; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी; राजदूत कृष्णन श्रीनिवासन; और श्री अंबरीश दासगुप्ता

कोलकाता में 11–12 मार्च, 2024 को मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (एमएकेएआईएएस), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनडीएलआई), बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई), और कोलकाता सोसाइटी फॉर एशियन स्टडीज (केएसएएस) के सहयोग से ''बंगाल की खाड़ी और भारत–जापान आर्थिक संबंध''विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत, जापान और बांग्लादेश के विद्वानों, व्यवसायियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों सहित 50 से अधिक वक्ताओं ने भारत–जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच उभरती त्रिपक्षीय साझेदारी के बारे में चर्चा की। इसके सत्रों में व्यापार, निवेश और मूल्य श्रृंखलाओं, नए क्षेत्रों में अवसरों का उपयोग करने के लिए सहयोग कायम करना और संबंधों को व्यापक बनाने के लिए चुनौतियों पर काबू पाने के मुद्दों पर चर्चा हुई।

सम्मेलन के तहत दो विशेष पैनल सत्र बदलती वैश्विक व्यवस्था में जापान–भारत साझेदारी तथा क्षेत्रीय विकास के लिए त्वरित साझेदारियों पर आयोजित किए गए। इन दो विशेष पैनलों के अलावा, सम्मेलन में पांच सत्र आयोजित किए गए, जिनमें औद्योगिक नीति और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; व्यापार, निवेश और मूल्य श्रृंखलाएं; लोगों के बीच परस्पर संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग जैसे सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में विचार–विमर्श किया गया। इन सत्रों में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय संबंधों की संभावनाओं तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जापान और भारत के बीच व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में भारत, जापान और बांग्लादेश के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करते हुए सम्मेलन के उद्देश्यों के बारे में बताया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राजदूत सुजान चिनॉय, महानिदेशक, एमपी–आईडीएसए ने की। उन्होंने भारत–जापान संबंधों, विशेषकर बंगाल के बारे में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य साझा किए। इसके अलावा, कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्यदूत श्री कोइची नाकागावा तथा विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पूर्वी एशिया प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री गौरांगलाल दास ने विशेष भाषण दिए। श्री नाकागावा ने कोलकाता के भू–रणनीतिक महत्व तथा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बांग्लादेश को जोड़ने वाली औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाएं बनाने और इस प्रकार आर्थिक एकीकरण को मजबूत बनाने की जापान की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया। श्री दास ने औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने और बांग्लादेश के साथ सहयोग, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित आर्थिक

शेष पृष्ठ 13 पर जारी...

भारत–इंडोनेशिया साझेदारी और नवीकृत समझ, नए अवसर

आरआईएस ने 17 जनवरी 2024 को भारत–इंडोनेशिया साझेदारीः बेहतर समझ, नए अवसर और भविष्य के महत्वपूर्ण कदम विषय पर हाइब्रिड मोड में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; राजदूत प्रीति सरन, पूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय; डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा, हबीबी सेंटर, इंडोनेशिया; प्रोफेसर शंकरी सुंदररमन, प्रोफेसर, सेंटर फॉर इंडो–पेसेफिक स्टडीज, एसआईएस, जेएनयू; और डॉ. पंकज वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस मुख्य वक्ता रहे। इसमें दोनों देशों के थिंक टैंक समुदाय के सदस्यों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा; राजदूत प्रीति सरन; प्रोफ़ेसर सुंदररमन; और डॉ. पंकज वशिष्ठ

प्रोफेसर चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में इस बात पर जोर दिया कि भारत और इंडोनेशिया ने असाधारण आर्थिक प्रगति हासिल की है और दोनों देश महत्वपूर्ण विकास साझेदार के रूप में भी उभरे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और इंडोनेशिया एक साथ काम करके बहुत कुछ कर सकते हैं।

राजदूत प्रीति सरन ने भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्व स्वीकार किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दिया। राजदूत सरन ने इंगित किया कि हालांकि रणनीतिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन द्वि पक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में व्यापार और निवेश महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पैनल के सदस्यों से भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के तरीके सुझाने का आग्रह किया।

डॉ. सतीश चंद्र मिश्रा ने 2000 के बाद से इंडोनेशिया की परिवर्तनकारी यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए इसे "कैटरपिलर से तितली" बनने के प्रणालीगत परिवर्तन के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एशिया की भू–राजनीति को नया आकार देने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट सुनियोजित सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। "चीन के कारक" के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में चीन की मौजूदगी है, लेकिन हालात जैसे दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। इंडोनेशिया भारतीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इंडोनेशियाई बाजार, खासकर उच्च संभावनाओं वाले स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढांचे में काम करने की कला सीखने की जरूरत है।

प्रोफेसर सुंदररमन ने इंडोनेशिया के बहुआयामी राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य का बारीकी से खाका पेश करने के लिए वहां के सामाजिक–धार्मिक संगठनों की भूमिका; सुकर्णो, सुहार्तो और मेगावती सुकर्णोपुत्री के नेतृत्व; इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली परिवारों की भूमिका; ग्लोबल मैरीटाइम फुलक्रम इनिशिएटिव; और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के संदर्भ में इंडोनेशिया–चीन संबंधों के बारे में चर्चा की। इंडोनेशिया का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य ऐतिहासिक विरासतों, विविध प्रभावों और रणनीतिक पहलों के जटिल परस्पर संबंधों को दर्शाता है, जो वैश्विक क्षेत्र में इसकी स्थिति को आकार देते हैं। इंडोनेशिया का ग्लोबल मैरीटाइम फुलक्रम इनिशिएटिव आर्थिक विकास, सुरक्षा और भूराजनीतिक प्रभाव के लिए अपने समुद्री भूगोल का लाभ उठाने की इंडोनेशिया की रणनीतिक दृष्टि को रेखांकित करता है।

डॉ. पंकज वशिष्ठ ने भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंधों की चर्चा की। हाल के उछाल के बावजूद, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा मुख्य रूप से प्रचलित उच्च गैर–टैरिफ बाधाओं, लंबी बहिष्करण सूचियों और एफटीए के कम उपयोग के कारण क्षमता से कम बनी हुई है। इन बाधाओं को हटाने से मौजूदा व्यापार की मात्रा में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दिलचस्प अवसर प्रदान करती है और उन्होंने इस बात की वकालत की कि दोनों देशों को मौजूदा समय में जारी डिजिटलीकरण से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सीमा पार ई–कॉमर्स और डिजिटल भुगतान लेनदेन की सुविधा के लिए नियामक ढांचे को सुसंगत बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए।

पैनल चर्चा का समापन उत्साहपूर्ण प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें सत्र के दौरान आर्थिक संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में हुई चर्चा के बारे में दर्शकों की सहभागिता और दिलचस्पी प्रदर्शित हुई। भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक साझेदारी की संभाव्यता का पता लगाने के लिए उनके बीच रणनीतिक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है।

आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाना

सत्र के दौरान मौजूद विशिष्ट प्रतिभागी

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के आसियान–भारत केंद्र ने 17 जनवरी 2024 को आरआईएस में "आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाना" विषय पर एक विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया। इस वैचारिक सत्र में राजदूत जयंत खोबरागड़े, आसियान में भारत के राजदूत के साथ प्रमुख विद्वानों, शिक्षाविदों और पूर्व राजनयिकों ने भाग लिया।

सत्र का आरंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के आरंभिक भाषण से हुआ। उन्होंने कहा कि आसियान–भारत मुक्त व्यापार समझौते ने आसियान–भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सुझाव दिया कि वर्तमान में जारी आसियान–भारत एफटीए की समीक्षा को इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी वकालत की कि आसियान और भारत को भविष्य को परिभाषित करने वाले फिनटेक और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

राजदूत खोबरागड़े ने अपने प्रारंभिक संबोधन में दलील दी कि भारत ने आसियान के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ गहन राजनयिक सहभागिता ने न केवल आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया है, बल्कि समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, जनता के बीच कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा आदि सहित कई अन्य क्षेत्रों में आसियान–भारत सहयोग को भी मजबूती प्रदान की है। राजदूत खोबरागड़े ने इस बात की ओर इंगित करते हुए अपनी बात समाप्त की कि शैक्षिक सहयोग में सुधार लाने के लिए आसियान–भारत विश्वविद्यालयों के नेटवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

राजदूत श्री खोबरागड़े के संबोधन के बाद आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के बारे में गहन चर्चा हुई। इस विचार–विमर्श के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये। भारत सीएलएमवी देशों में त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं लागू कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मेजबान देशों के साथ–साथ भारत के लिए इन परियोजनाओं की दक्षता, प्रभावकारिता और उपयोगिता की जांच करने के लिए इन परियोजनाओं का ऑडिट कराया जाना चाहिए। आसियान और व्यापक हिंद–प्रशांत के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।

प्रतिभागियों की दलील थी कि भारत जिन प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की चर्चा कर रहा है, उन्हें मूर्त रूप प्रदान करने के लिए लगभग 80 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। हालांकि, प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए केवल 8 बिलियन डॉलर ही हासिल किए गए हैं। धन की इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार को समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। समावेशी विकास के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप का महत्व तथा इन क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच गहन सहयोग की वकालत की गई।

समुद्री क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा करते हुए प्रतिभागियों ने दलील दी कि यद्यपि यूएनसीएलओएस सहित महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के संबंध में आसियान और भारत के बीच वैचारिक समानता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, जो ध्यान भटका सकते हैं। आसियान के विपरीत, भारत ने 'हाई सी संधि' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण भविष्य में ध्यान भटक सकता है। आसियान के साथ काम करते समय सरकार को इस संभावित ध्यान भटकाने वाले बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सांस्कृतिक ओवरलैप को अनुकूलित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

प्रतिभागियों ने भारत के नीतिगत दृष्टिकोण के विकास के बारे में विचार–विमर्श करते हुए लुक ईस्ट नीति में बदलाव लाकर अधिक व्यापक हिंद–प्रशांत नीति का सुझाव दिया गया। उन्होंने बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य को भी स्वीकार किया और नीतियों को उभरते क्षेत्रीय बदलावों के अनुरूप ढालने की वकालत की।

अंततः, इस सत्र ने गहन विचार–विमर्श का एक मंच प्रदान किया, जिसमें आसियान–भारत साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आईं। इस बहुआयामी संवाद में आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल रहे, जिनमें उभरते हिंद–प्रशांत संदर्भ में चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों को अनुकूलित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

20वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलनः परिणामों से कार्यान्वयन तक

संगोष्ठी में मौजूद विशिष्ट वक्ता

आरआईएस में 8 फरवरी 2024 को "20वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलनः परिणामों से कार्यान्वयन तक" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विषय के जानकारों ने आसियान–भारत साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में विचार–विमर्श किया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आसियान में भारत के राजदूत जयंत एन. खोबरागड़े ने मुख्य भाषण दिया, भारत और भूटान में इंडोनेशिया की राजदूत महामहिम सुश्री इना एच. कृष्णमूर्ति सम्मानित अतिथि रहीं। वक्ताओं ने सुझाव दिया कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए आसियान–भारत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर बातचीत और ठोस कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

राजदूत राजीव भाटिया, प्रतिष्ठित फेलो, गेटवे हाउस ने 12–सूत्रीय प्रस्ताव के महत्व और कार्यान्वयन के संबंध में एक सत्र की अध्यक्षता की। राजदूत ओंग केंग योंग और डॉ. वेंकटचलम अंबुमोझी ने विषय की व्यापक समझ में योगदान देते हुए बहुमूल्य अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने सुरक्षा से संबंधित पारंपरिक और गैर–पारंपरिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तावित उपायों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। चर्चा का एक अन्य केंद्र बिंदु खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की अनिवार्यता रहा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की उप महानिदेशक डॉ. जोआना केन–पोटाका ने सत्र की अध्यक्षता की, डॉ. फातिमा मोहम्मद अरशद और डॉ. कल्पना शास्त्री आर. जैसे सम्मानित वक्ताओं के अनुभवों के साथ प्रतिभागियों ने आसियान–भारत श्रीअन्न महोत्सव, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में आसियान–इंडिया ग्रीन फंड और आसियान–भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। चर्चाएं कृषि चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और निवेश के उपयोग के ईद–गिर्द केंद्रित रहीं। समुद्री सुरक्षा से संबंधित गैर–पारंपरिक खतरों को दूर करना भी चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र की अध्यक्षता में सत्र के अंतर्गत कैप्टन सरबजीत परमार और डॉ. एरी अफ्रिंसयाह सहित विशेषज्ञों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए। वक्ताओं ने दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रमों सहित समुद्री सुरक्षा पर भू–राजनीतिक मुद्दों के प्रभाव के बारे में चर्चा की। स्थायी समुद्री संसाधन सुनिश्चित करने और भू–राजनीतिक चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। विषयों की विविधतापूर्ण श्रृंखला में आसियान–भारत सहयोग की बहुआयामी प्रकृति और क्षेत्रीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास शामिल रहे।

इस संगोष्ठी ने आसियान–भारत साझेदारी के जटिल पहलुओं के बारे में गहरी समझ को बढ़ावा देते हुए प्रबल विचार–विमर्श के एक मंच के रूप में कार्य किया। इससे प्राप्त समझ से भागीदार देशों के पारस्परिक लाभ के लिए नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है।

कृषि के संबंध में दक्षिण आभासी कार्यशाला

दक्षिण ने 17 जनवरी 2024 को कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला ने ग्लोबल साउथ में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों पर विचार–मंथन के एक मंच के रूप में कार्य किया और इस क्षेत्र की चुनौतियों के संभावित समाधानों का एक सार–संग्रह संकलित करने में दक्षिण को एक कदम आगे बढ़ाया।

इस आभासी कार्यशाला का उद्देश्य : कृषि क्षेत्र में नवोन्मेषी समाधानों, सर्वोत्तम प्रथाओं, भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की सफल प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करना;इन देशों द्वारा समर्थित विकास समाधानों को बढ़ावा देना, ताकि तीसरी दुनिया के साथी देशों द्वारा संभावित रूप से इन्हें दोहराया और अपनाया जा सके। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आपसी सीख, अनुभवों के आदान–प्रदान और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को भी शामिल करना; और सामान्य हितों और संस्थागत सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना था।

इस आभासी कार्यशाला में समूचे ग्लोबल साउथ, फिजी से लेकर चिली तक और ग्लोबल साउथ के अन्य सभी देशों के पैनल के सदस्य, विषय से संबंधित विशेषज्ञ और 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला की शुरुआत भारतीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रस्तुति के साथ हुई, इसके बाद सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों: खाद्य सुरक्षा और पोषण; टिकाऊ, समावेशी और जलवायु–अनुकूल कृषि; कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण और कृषि बाजारों का डिजिटलीकरण के बारे में ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की ओर से जानकारी प्राप्त हुई।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, समाधानों पर जोर देते हुए

विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता है। उन्होंने हितधारकों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा समाधानों और साझा अनुभवों में शामिल होने का आह्वान किया और ग्लोबल साउथ में कृषि क्षेत्र से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में एक पुस्तिका लाने की सिफारिश की।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. स्मिता सिरोही ने अपने मुख्य भाषण में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि आजीविका को समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने तथा अनुकूल एवं टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्यों को रेखांकित किया। उन्होंने स्थिरता, जोखिम प्रबंधन, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और लाभकारी खेती के लिए जलवायु–अनुकूल फसलों के विकास की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों को साझा किया। प्रस्तुतत किए गए प्रमुख भारतीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –पीएमएफबीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि अवसंरचना कोष फंड (एआईएफ), किसान–उत्पादक संगठन (एफपीओ), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम), एग्री–स्टैक और किसानों के लिए मोबाइल टेलीफोनी शामिल हैं। उन्होंने समूचे ग्लोबल साउथ में कृषि क्षेत्र की समान चुनौतियों से निपटने के लिए एक–दूसरे से सीखने की आवश्यकता का समर्थन किया।

बालाजी विद्यापीठ के उपाध्यक्ष डॉ. एस. आर. राव ने विशेषकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में न्यायसंगतता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समूचे ग्लोबल साउथ के देशों में उपयुक्त कंपनियों और हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया।

अघुब की प्रबंध निदेशक डॉ. कल्पना शास्त्री ने हाल के वर्षों में कृषि–स्टार्ट–अप विकसित करने की दिशा में हासिल गति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उभरते कृषि स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सक्षम एजेंसियों की आवश्यकता है। उनकी चर्चा में जैव–अर्थव्यवस्था, पुनरुत्पादक कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को साकार करना भी शामिल रहा।

समूचे ग्लोबल साउथ के थिंक टैंकों ने

एक समर्पित सत्र में अपने अनुभव साझा किए। एबोनी सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (ईसीएसएस) के प्रबंध निदेशक डॉ. लुआल ए. डेंग ने दक्षिण सूडान से संबंधित अपने अनुभव साझा किए जिनमें– मौसम की चरम घटनाओं के बीच भूमि का अल्प उपयोग, कृषि शिक्षा की कमी और खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए भूमि के बेहतर उपयोग हेतु एआई में निवेश का अभाव शामिल है। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय परिवर्तन पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।

जाम्बिया इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च (जेडआईपीएआर), जाम्बिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. हेरिक मपुकु ने मुख्यतः वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता और सिंचाई की सुविधाओं के अभाव, खराब बुनियादी सुविधाओं और बाजार की सूचना, वित्त और बीमा के अभाव के कारण उत्पादकता कम होने जैसी कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने सिंचाई प्रणालियों, सड़कों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि सहित गुणवत्तापूर्ण इनपुट की आपूर्ति तथा बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता को समाधान के रूप में सुझाया। उन्होंने कृषि बाजारों में निजी क्षेत्र की भूमिका और विस्तार सेवाओं में सुधार और पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकियों और अनुभवों के बारे में सूचना का आदान–प्रदान करने तथा एक–दूसरे से सीखने के लिए दक्षिण जैसे पारस्परिक प्रभाव वाले मंच के महत्व पर भी जोर दिया।

पूर्वी कैरेबियाई देशों (ईसीएस) में इंटर–अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर (आईआईसीए) के प्रतिनिधि श्री ग्रेग सी. ई. रॉलिन्स ने स्कूली भोजन कार्यक्रमों और पोषण के लिए स्कूल उद्यानों से संबंधित अपने काम पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाधानों को किसान–केंद्रित बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और दक्षिण द्व ारा ग्लोबल साउथ में ज्ञान साझा करने की दिशा में निभाई जाने वाली भूमिका की सराहना की।

टोंगा साम्राज्य के रॉयल ओशिनिया इंस्टीट्यूट (आरओआई) की मुख्य परिचालन अधिकारी लेडी फेन फाकाफानुआ ने टोंगा साम्राज्य में जोत के छोटे आकार, बाजार दूर–दराज के इलाकों में होने और सिंचाई प्रणालियों का अभाव होने जैसे मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने विलवणीकरण और अन्य परियोजनाओं पर आने वाली भारी–भरकम लागतों को भी रेखांकित किया और बताया कि अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ कृषि वस्तुओं के व्यापार की चुनौतियों से निपटने के लिए देश में बहु–फसल प्रणाली का अभ्यास किया जाता है।

इस दौरान हुई चर्चाएं बहुत दिलचस्प और ज्ञानवर्धक रहीं। डॉ. करीम एम. मारेडिया, निदेशक, वर्ल्डटीएपी, एमएसयू, अमेरिका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि उत्पादन से कृषि विपणन का रुख कर रही है तथा उन्होंने कृषि विकास के लिए आउटरीच और विस्तार सेवाओं की बढ़ती भूमिका की वकालत की। उन्होंने जल संरक्षण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि युवा कृषि से दूर हो रहे हैं और उन्हें कृषि से जोड़े रखने के लिए अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुक्त चर्चा सत्र में बोलने वाले कई अन्य लोगों की ही तरह वैश्विक ज्ञान साझेदारी और सहयोग विकसित करने की पहल की सराहना की।

कार्यशाला बहुत सकारात्मक रुख के साथ समाप्त हुई, हितधारकों और प्रतिभागियों ने आने वाले दिनों में दक्षिण के प्रयासों में योगदान देने की प्रतिबद्ध ता दोहरायी। इसमें प्राप्त जानकारी ग्लोबल साउथ में समावेशी विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देते हुए आगामी प्रथम दक्षिण सम्मेलन के लिए महत्वपूर्ण आधार का काम करेगी।

वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना

दक्षिण की स्वास्थ्य क्षेत्र पर दूसरी ऑनलाइन कार्यशाला 2 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई। इस ई–कार्यशाला में ग्लोबल साउथ के अनेक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) की अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता की तथा भारत और ग्लोबल साउथ में स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य रूप से और कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बसंत गर्ग ने मुख्य भाषण दिया तथा ऐसे सफल और नवोन्मेषी भारतीय स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें ग्लोबल साउथ के अन्य देशों में दोहराया और प्रसारित किया जा सकता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रोग्राम एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशंस की निदेशक

सुश्री अर्चना व्यास ने बताया कि स्वास्थ्य कूटनीति और स्वास्थ्य क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना और अन्य देशों के साथ साझा किए जा रहे सबक के बारे में सकारात्मक विचार प्रकट किए। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) की उपाध्यक्ष डॉ. प्रीति कुमार ने इस बात का उल्लेख किया कि विशेष कर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से पब्लिक हेल्थ केयर में परिवर्तन के लिए स्पष्ट आह्वान की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य से कल्याण की दिशा में परिवर्तन केवल तभी किया जा सकता है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों को समुदायों की भली–भांति सेवा करने के लिए सही मात्रा में ज्ञान और कौशलों के साथ शिक्षा प्रदान करके स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में शामिल किया जाए। अल साल्वाडोर के सोशल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेसी के कार्यकारी निदेशक रेमन विलाल्टा ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखरेख मूलभूत आवश्यकता है। अल साल्वाडोर ने महामारी के दौरान, विशेष रूप से देश के मूल निवासियों के समुदायों में टीके के प्रति झिझक समाप्त करने के लिए एक मॉडल का इस्तेमाल किया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सेंटर फॉर इक्विटी एंड ग्रोथ (सीआईपीपीईसी), अर्जेंटीना की सुश्री कैरोलिना कैसुलो ने कहा कि अर्जेंटीना में डिजिटल स्वास्थ्य में सबसे अच्छी पद्धति बाहरी वित्तपोषण द्वारा समर्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना विभाग का सृजन रहा। हालांकि, अर्जेंटीना में स्वास्थ्य सेवाओं के न्यायसंगत वितरण का अभाव होने की चुनौती मौजूद है। यह कार्यशाला प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति में होने वाले आगामी दक्षिण सम्मेलन में इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ सकारात्मक रुख के साथ समाप्त हुई।

डिजिटल समाधानों के संबंध में कार्यशाला

दक्षिण–ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 28 फरवरी, 2024 को डिजिटल समाधानों के संबंध में अपनी तीसरी ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें ग्लोबल साउथ के अनेक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में दक्षिण के विजन और मिशन के बारे में जानकारी प्रदान की।

कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्रालय के डीपीए–प्प्प प्रभाग में संयुक्त सचिव श्री रोहित रथीश ने भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में डिजिटल उपकरणों की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत के सहयोग, उन्हें बिना किसी खर्च के और ओपन–सोर्स एक्सेसिबिलिटी के साथ इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) प्रदान करने के बारे में चर्चा की। डिजिटल समाधानों के साथ भारत के अनुभवों के बारे में श्री सौरभ कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव, डीबीटी मिशन, कर्नल निखिल सिन्हा, निदेशक (प्रवर्तन), यूआईडीएआई, श्री नितिन मिश्रा, सीटीओ ओएनडीसी, श्री अजय कुमार चौधरी, गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक, एनपीसीआई और प्रोफेसर एस राजगोपालन, मानद् विजिटिंग फैकल्टी, आईआईआईटी बैंगलोर सहित भारतीय विशेषज्ञों ने जानकारी साझा की।

मॉरीशस के एएसएआरपीआई के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जॉन हस्टन स्टैनफील्ड, सर्बिया के आईआईपीई में रिसर्च फेलो डॉ. एलेक्जेंड्रा तोसोविक–स्तेवानोविक, बोत्सवाना में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अफ्रीका के संस्थापक श्री योरोकी कपिम्बुआ और अल साल्वाडोर में आईएसडी के निदेशक श्री होजे रामोन विलाल्टा, सभी ने डिजिटल समाधानों में संलग्न भारतीय एजेंसियों की विस्तृत प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने डिजिटल समाधानों की संभावित उपयोगिता पर जोर देते हुए अपने–अपने देशों के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी चर्चा की। प्रोफेसर जॉन हस्टन स्टैनफील्ड और श्री योरोकी कपिम्बुआ ने अपनी प्रस्तुतियों में डिजिटल समाधानों के व्यावहारिक निहितार्थ और उन्हें लगाने पर आने वाली लागत पर जोर दिया, जबकि डॉ. एलेक्जेंड्रा तोसोविक–स्तेवानोविक और श्री होजे रामोन विलाल्टा ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर चर्चा की।

वैश्विक सहयोग की संभावनाएं तलाशना

एपीआरआई, आर्मेनिया की अध्यक्ष सुश्री लारा सेट्रैकियन, सीनियर रिसर्च फेलो बेन्यामिन पोघोस्यान और एसोसिएट फेलो श्री डेविट एंटोनियन ने 22 फरवरी, 2024 को आरआईएस का दौरा किया और दक्षिण के साथ सहयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने एमईआईटीवाई के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन की सहायता से इंडिया स्टैक पहल के अंतर्गत एपीआरआई के विशेषज्ञों को उनके भारतीय समकक्षों के साथ जोड़ने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने पारगमन और परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु वित्त, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, कृषि–तकनीक आदि जैसे मुद्दों पर भी दक्षिण के साथ काम करने की इच्छा प्रकट की।

सीआरपीएम के अध्यक्ष प्रोफेसर ज़िदास दस्कालोव्स्की और कार्यकारी निदेशक डॉ. मारिजा रिस्टेस्का ने 23 फरवरी 2024 को आरआईएस में दक्षिण का दौरा किया और आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और अन्य हस्तियों के साथ दोनों संस्थानों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। ईआरएएसएमयूएस जैसे शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम की स्थापना करना और दक्षिण के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की संभावनाएं तलाशने जैसे विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया

राजदूत डॉ. फरीद शफीयेव, अध्यक्ष और वासिफ हुसैनोव, शाखा प्रबंधक, एआईआर सेंटर, अजरबैजान ने अजरबैजान के राजदूत श्री एलचिन हुसैनली के साथ 23 फरवरी को आरआईएस में दक्षिण का दौरा किया और साझा सहयोग की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने यूएनएफसीसीसी सीओपी 29 से जुड़े मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम करने तथा शहरी विकास, कृषि और जल के अभाव के बारे में दक्षिण के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। मिस्र के ईसीईएस के कार्यकारी निदेशक और अनुसंधान निदेशक डॉ अबला अब्देल लतीफ ने आरआईएस, दक्षिण में जीडीसी फेलो श्री अतुल कौशिक के साथ दक्षिण के साथ संभावित सहयोग के बारे में चर्चा की। डॉ. लतीफ़ ने संयुक्त प्रयासों के लिए विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने और मिलकर वित्त प्राप्त करने के उद्देश्य से छोटे किसानों के लिए कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर एक कार्यशाला का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राजदूत विजय कांत कर्ण, कार्यकारी अध्यक्ष, सीईएसआईएफ, नेपाल ने 29 फरवरी को आरआईएस में दक्षिण का दौरा किया। उन्होंने नागरिकों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने तथा इसमें किसी तरह का विलंब और लीकेज रोकने में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में भारतीय अनुभवों को जानने में दिलचस्पी व्यक्त की।

51वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान

भविष्य की फसलें विकसित करने के लिए सीआरआईएसपीआर

51वां एसटीआईपी फोरम सार्वजनिक व्याख्यान 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में प्रोफेसर के.सी. बंसल, पूर्व निदेशक, आईसीएआर–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एवं सदस्य, न्यासी बोर्ड, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने दिया। इस व्याख्यान का विषय "भविष्य की फसलों के विकास के लिए सीआरआईएसपीआर" था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टेरी की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने की। स्वागत भाषण इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने दिया।

प्रोफेसर बंसल ने अपने बहुत ही ज्ञानवर्धक और दूरदर्शी व्याख्यान में, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरआईएसपीआर जैसी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकियों के उपयोग के दायरे, क्षमता और संभावनाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधनों, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों के बीच भविष्य में भोजन की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए अपने व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और आर्थिक विकास से जुड़े आहार परिवर्तन के कारण 2050 तक 50 प्रतिशत अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, वांछित गुणों के साथ फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीनोम संपादन का उपयोग किया जा सकता है। वांछित गुण कृषि संबंधी (जैसे कि कीट प्रतिरोध, शाकनाशी सहनशीलता, सूखा प्रतिरोध, लवणता सहनशीलता, उच्च उपज आदि) के साथ ही साथ जैव–फोर्टिफाइड फसलों आदि जैसे पोषण गुणवत्ता गुण हो सकते हैं।

प्रोफेसर बंसल ने जीनोम संपादन से संबंधित विनियामक परिदृश्य और दुनिया भर में जीनोम संपादित फसल उत्पादन की मौजूदा स्थिति का उल्लेख किया और भारत सरकार के दो ऐतिहासिक

प्रोफेसर के.सी.बंसल व्याख्यान दे रहे हैं

नीतिगत निर्णयों अर्थात 'जैव–सुरक्षा मूल्यांकन (मार्च 2022) से जीनोम संपादित फसलों (एसडीएन1 और एसडीएन2) की छूट' और 'जीएम सरसों हाइब्रिड की पर्यावरणीय रिलीज (अक्टूबर, 2022)' की सराहना की। उन्होंने दलील दी कि ये नीतिगत निर्णय भारतीय कृषि क्षेत्र

शेष पृष्ठ 17 पर जारी...

बिम्सटेक के महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे का आरआईएस का दौरा

बिम्सटेक के महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे ने एक इंटरैक्टिव सत्र के लिए बुधवार, 6 मार्च, 2024 को आरआईएस का दौरा किया। उनके इस दौरे का उद्देश्य बिम्सटेक और आरआईएस के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और बिम्सटेक की कार्य संरचना और क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करना था।

यह सत्र मुख्य रूप से ढाका स्थित बिम्सटेक सचिवालय और आरआईएस के साथ ही साथ विदेश मंत्रालय (एमईए) भारत; विदेश मंत्रालय (एमओएफए), बांग्लादेश और अन्य बिम्सटेक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित था। भूटान, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ सहयोग पर बल दिया गया। बैठक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। इस बैठक ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के भीतर साझा हितों को आगे बढ़ाने में बहुपक्षीय सहभागिता के महत्व को भी रेखांकित किया। इस इंटरैक्टिव सत्र में आरआईएस संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे विचारों और अनुभवों का उपयोगी आदान–प्रदान सुगम हुआ।

प्रौद्योगिकी और समाज के अन्तर्सम्बंधों की तलाश

ऋषिहुड विश्वविद्यालय के लगभग 130 विद्यार्थियों ने कुलपति प्रोफेसर शोभित माथुर के साथ 'प्रौद्योगिकी और समाज' से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए 2 फरवरी 2024 को आरआईएस का दौरा किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर चतुर्वेदी ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों से संबंधित एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में आरआईएस की कार्ययोजना की जानकारी देते हुए स्वागत भाषण दिया। उन्होंने विशेषकर प्रौद्योगिकी नेतृत्व के संदर्भ में भारत के विकसित होते विकास परिप्रेक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला। आरआईएस के अनेक संकाय सदस्यों ने विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी और समाज के बीच इंटरफेस के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अवगत कराया। एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पी. दाश ने भारत पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने फिनटेक द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली और वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में मदद करने वाली कुछ प्रमुख नवोन्मेषी अनुकूलित सेवाओं के बारे में जानकारी साझा की। विजिटिंग फेलो डॉ. पी.के. आनंद ने सामाजिक–आर्थिक विकास और प्रणालीगत परिवर्तनों में

सत्र जारी है

तेजी लाने के सशक्त साधन के रूप में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एसडीजी हासिल करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी बल दिया। प्रतिष्ठित फेलो डॉ. जे. आर. भट्ट ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के बारे में चर्चा की। उन्होंने धरती पर सजीव और निर्जीव दोनों के स्थायी सह–अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण सम्मत जीवन शैली की अवधारणा के बारे में भी चर्चा की। सलाहकार डॉ. आर. श्रीनिवास ने उभरती प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करते हुए समाज के लिए उनके प्रभाव और संभावित प्रभावों को रेखांकित किया। सलाहकार डॉ. नम्रता पाठक ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था, व्यापार और निवेश, सतत विकास लक्ष्यों और अधिकारों पर आधारित अन्य सामाजिक–आर्थिक ढांचों के संदर्भ में पारंपरिक चिकित्सा के विषय पर विचार प्रस्तुत किए। सलाहकार डॉ स्नेहा. सिन्हा ने विज्ञान कूटनीति के विषय पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग से 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाली समान चुनौतियों से निपटा जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए आयुष मंत्रालय और आरआईएस के बीच समझौता ज्ञापन

आयुष मंत्रालय और आरआईएस ने 27 फरवरी, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर अपने सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया। इस समझौते का उद्देश्य अकादमिक सहयोग बढ़ाना और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, नीतिगत संवाद और प्रकाशन को सुगम बनाना है। इस समझौता ज्ञापन पर आयुष मंत्रालय की ओर से सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, जबकि आरआईएस की ओर से महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने हस्ताक्षर किए।

वैद्य राजेश कोटेचा और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

यह समझौता ज्ञापन आयुष सेवा क्षेत्र में अनुसंधान, नीतिगत विकास और क्षमता निर्माण के लिए अकादमिक सहयोग मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसमें फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) को बनाए रखना शामिल है। सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने एफआईटीएम के बहुमूल्य योगदान पर जोर देते हुए आयुष मंत्रालय और आरआईएस के बीच दीर्घकालिक सहयोग को स्वीकार किया। उन्होंने आयुष विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित करते हुए आयुष सेवा क्षेत्र के संबंध में भी ऐसा ही रहने की आशा व्यक्त की। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाजार के अनुमानों, उत्पाद मानकीकरण और नियमों के बारे में विस्तृत रूपरेखा प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनने की आयुष क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करते हुए इस संबंध में रोडमैप विकसित करने में आरआईएस की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने जैव विविधता के उपयोग और सुरक्षा की दोहरी भूमिका पर जोर देते हुए जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में नवोन्मेषी विचारों का समर्थन किया। आयुष मंत्रालय और आरआईएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अकादमिक सहयोग को मजबूत बनाने और आयुष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आरआईएस की 'सीईओ स्पीक्स' श्रृंखला

आरआईएस ने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और थिंक टैंकों के बीच सहयोग और ज्ञान का आदान–प्रदान करने के एक रोमांचक अवसर के रूप में 'सीईओ स्पीक्स' श्रृंखला का शुभआरंभ किया गया। 'सीईओ स्पीक्स' श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के प्रमुख आपसी तालमेल को बढ़ावा देने और नीति–निर्माण की प्रक्रियाओं में योगदान बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे।

श्रृंखला का पहला व्याख्यान शुक्रवार, 9 फरवरी 2024 को आरआईएस में आईसीआरआईईआर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी डॉ. दीपक मिश्रा ने दिया। डॉ. मिश्रा ने अंत:विषयक अनुसंधान विषयों पर विचार करने के लिए आईसीआरआईईआर और आरआईएस के साथ–साथ अन्य थिंक टैंकों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम में आरआईएस के शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

डॉ. मिश्रा ने सुझाव दिया कि आईसीआरआईईआर और आरआईएस अन्य थिंक टैंक के साथ, कृषि नीति, स्थिरता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और नवाचार जैसे अंत:विषयक विषयों पर विचार करने वाले संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों पर मिलकर काम कर सकते हैं। विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के बीच विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुसंधान निष्कर्षों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के साधन के रूप में संयुक्त सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन पर बल दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार के साथ कृषि नीति का अंतर्संबंध, या जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और स्थिरता के बीच संबंध जैसे बहु–विषयक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सहयोगात्मक अनुसंधान समूहों या कार्य बलों की स्थापना का विचार सामने रखा गया।

बहु–विषयक टीमें बनाने के लिए डॉ. मिश्रा ने विभिन्न पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों को एक साथ लाने के महत्व पर जोर दिया। ये टीमें जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने वाली समग्र अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रस्तुत कर सकती हैं। प्राप्त होने वाले उल्लेखनीय सुझावों में जी–20 संस्थाओं, ब्रुकिंग्स, आईसीआरआईईआर, आरआईएस और समान विचारधारा वाली संस्थाओं को शामिल करते हुए एक क्रॉस–थिंक टैंक समुदाय का गठन किए जाने का सुझाव शामिल था।

ग्लोबल साउथ में मानव विकास को बढ़ावा देना

आरआईएस ने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवेलपमेंट (आईएचडी) और नीति आयोग के सहयोग से 11–13 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में "ग्लोबल कॉन्क्लेव 2024: ग्लोबल साउथ में मानव विकास को बढ़ावा देना" विषय पर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में लगभग 350 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विकास व्यवसायियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। पूरे सम्मेलन के दौरान आरआईएस ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया और उनका आयोजन किया।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ग्लोबल कॉन्क्लेव 2024 में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं

सम्मेलन से पूर्व 10 जनवरी 2024 को एक कार्यक्रम में आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र, भारत और आईएचडी के सहयोग से 'वैश्विक समृद्धि के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना' विषय पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि ग्लोबल साउथ दुनिया में अपनी मजबूत व्यापक आर्थिक अधोसंरचना और अपनी बढ़ती भूमिका के आधार पर उभर रहा है और परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयाम लाने जा रहा है। इस गहन चर्चा में विषय से संबंधित कई अन्य विशेषज्ञों जैसे श्री शोम्बी शार्प, डॉ. अभिलाषा जोशी, राजदूत श्याम सरन, डॉ. अनु पेलटोला, डॉ. क्रिश्चियन क्यूवास, डॉ. राजेश टंडन, डॉ. इब्राहिम अवाद, डॉ. अजीता बरार, डॉ. इमरान वालोदिया और प्रोफेसर अलख शर्मा ने भाग लिया। इस चर्चा के दौरान दक्षिण–दक्षिण सहयोग के महत्व को स्वीकार किया गया। इस बारे में चर्चा की गई कि दक्षिण की भूमिका को प्रायः पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वैश्विक मंचों पर इस बारे में समुचित रूप से विचार नहीं किया गया। पैनल ने हाल ही में जी–20 की अध्यक्षता के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने और एसडीजी को अंतरराष्ट्रीय मंच के केंद्र में रखने के संबंध में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। राजदूत सरन ने वैश्विक निर्यात का 47 प्रतिशत हिस्सा कवर करने वाले विकासशील देशों के आर्थिक प्रोफ़ाइल पर जोर देते हुए कहा कि जल्द ही विकासशील देशों से ही विकास को गति मिलने की संभावना है। पैनल के सदस्यों ने विकास से संबंधित अन्य सहायता के साथ–साथ सतत विकास के लिए भी दक्षिण–दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। दक्षिण–दक्षिण सहयोग के दायित्व को आगे बढ़ाने में सिविल सोसायटी की भूमिका कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है। सत्र में विशिष्ट चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन, औद्योगीकरण, श्रम बल और प्रवासन जैसे क्षेत्रों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मेक्सिको के मामले के समान ज्ञान साझा करने और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए डेटा संग्रह के महत्व पर भी जोर दिया गया।

मुख्य कार्यक्रम के दौरान आरआईएस ने तीन सत्र आयोजित किए, जिनमें से एक सत्र पर्यावरण सम्मत जीवन शैली: एक वैकल्पिक विकास परिप्रेक्ष्य की ओर' की अध्यक्षता प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी की तथा प्रोफेसर सीता प्रभु, प्रोफेसर थॉमस पोगे, प्रोफेसर दनांग परिकेसिट, प्रोफेसर पम्मी दुआ और डॉ शैली केडिया जैसे विशेषज्ञों को पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने भारत की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान एचएलपी को अपनाए जाने को रेखांकित करते हुए सीओपी 26 में लॉन्च से लेकर एक व्यापक विकास मॉडल बनने तक की लाइफ की यात्रा की पड़ताल की। सत्र में 1970 के दशक के बाद से विकास के परिप्रेक्ष्यों को नया आकार देने में ग्लोबल साउथ की भूमिका पर भी चर्चा की गई। प्रोफेसर थॉमस पोगे, ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम के निदेशक तथा दर्शनशास्त्र और राजनीति विज्ञान के लीटनर प्रोफेसर, येल यूनिवर्सिटी, अमेरिका ने नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए, 4–आयामी दृष्टिकोण:कानूनी ढांचा, बुनियादी ढांचा, विकल्प और विश्वास तथा प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से एक नए परिप्रेक्ष्य की वकालत की। उन्होंने नवाचार की भूमिका पर जोर देते हुए निधियों को प्रभावित करने के लिए एकाधिकार मार्कअप के बजाय लाभ पर ऑपरेट करने वाली पारंपरिक आईपीआर व्यवस्थाओं से आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा। प्रोफेसर सीता प्रभु, विजिटिंग प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवेलपमेंट, नई दिल्ली और पूर्व प्रमुख, ह्यूमन डेवेलपमेंट रिसोर्स सेंटर, यूएनडीपी, नई दिल्ली, ने 3 ई : एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकॉनोमी (यानी पर्यावरण, रोजगार और अर्थव्यवस्था) और 3 सी: कल्चर, कम्युनिटी एंड च्वॉसेज (यानी संस्कृति, समुदाय और विकल्प) पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाइफ के परिप्रेक्ष्य और मानव विकास के परिप्रेक्ष्य के बीच समानताएं गिनाईं। वर्तमान आर्थिक मॉडल की खामियों पर प्रकाश डालते हुए,

शेष पृष्ठ 17 पर जारी...

विज्ञान कूटनीतिः मुद्दे, नीतिगत विकल्प और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को आयोजित 'विज्ञान कूटनीतिः मुद्दे, नीतिगत विकल्प और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से एक व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने भारत के विकास संबंधी सहयोग के सिद्धांतों और तौर–तरीकों पर जोर दिया।

उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत के विकास संबंधी सहयोग के सबसे आवश्यक सिद्धांतों में से एक बिना किसी तरह की शर्त के सहयोग का कार्यक्रम तैयार करना, परस्पर सम्मान, विविधता, भविष्य की देखभाल और सतत विकास द्वारा संचालित साझेदारियां कायम करना है। उन्होंने 1947–2022 के दौरान भारत की 107 बिलियन डॉलर की व्यापक विकास सहायता तथा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने सीईआरएन, आईटीईआर, एफएआईआर आदि जैसी विशाल–विज्ञान परियोजनाओं में भारत की भागीदारी के महत्व और हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे में शामिल होने के बारे में भी चर्चा की।

प्रोफेसर चतुर्वेदी ने भारत के नेतृत्व वाली कुछ प्रमुख विज्ञान कूटनीति पहलों जैसे 1983 में स्थापित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी), 2015 में आरंभ किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और 2019 में स्थापित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ब्रिक्स, बिम्सटेक, आसियान आदि जैसे मंचों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत के बहुपक्षीय सहयोग और 80 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इंडो–यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (आईयूएसएसटीएफ), सीईएफआईपीआरए और इंडो–जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के उदाहरण भी दिए। भारत द्वारा की गई अनेक पहलों के बीच प्रोफेसर चतुर्वेदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की ओर से चुनिंदा देशों के साथ निकट एसटीआई सहयोग सुगम बनाने के लिए चार देशों अर्थात् रूस, जापान, अमेरिका और जर्मनी में विज्ञान परामर्शदाताओं को भेजा गया है।

उन्होंने मौजूदा विज्ञान कूटनीति के ढांचे की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हुए इसकी सीमाओं पर प्रकाश डाला क्योंकि यह ग्लोबल नॉर्थ के अनुभवों पर आधारित है और इसमें 'सॉफ्ट पावर' का तत्व मौजूद है। उन्होंने विज्ञान कूटनीति के लिए एक ऐसे नए शब्दकोश की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो ग्लोबल साउथ की जरूरतों और मांगों पर गौर करता हो। उन्होंने अपने व्याख्यान में विज्ञान कूटनीति की भूमिका और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य के महत्व पर भी जोर दिया।

पृष्ठ 2 से जारी...

संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित हुए जापानी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की क्षमता को रेखांकित किया, जो दोनों देशों के आर्थिक बहाली के लिए महत्वपूर्ण है। आरआईएस के प्रोफेसर डॉ. प्रबीर डे ने सम्मेलन के आयोजन के प्रेरणा के बारे में चर्चा करते हुए धन्यवाद ज्ञापन ज्ञापित किया।

विभिन्न प्रख्यात वक्ताओं ने भारत और जापान के संबंधों को मजबूत बनाने के बारे में अपने प्रमुख विचार और नीतियां सामने रखीं। जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने भारत–जापान संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण ढांचे, मानव संसाधन प्रबंधन, हरित अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार और परिवहन तथा पर्यावरण–अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया। राजदूत कृष्णा श्रीनिवासन, भारत के पूर्व विदेश सचिव ने भी पर्यटन, व्यापार, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर जोर दिया। ओसाका में भारत के महावाणिज्य दूत श्री निखिलेश गिरि ने अपने विशेष भाषण में जनता के बीच आपसी संबंधों में अधिक निवेश सहित दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों के लिए टोक्यो और नई दिल्ली जैसे मुख्य शहरों से परे देखने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. अशोक चावला, सलाहकार, विदेश मंत्रालय ने अपने समापन भाषण में दोनों देशों की जनता के आपसी रिश्तों और व्यवसायों के बीच संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. चावला ने कहा कि त्रिपक्षीय सहयोग में सुधार की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं और भारत–जापान एक्ट ईस्ट फोरम, भारत और जापान के बीच व्यापक सहभागिता सुगम बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इस सम्मेलन में प्रोफेसर राधारमण चक्रवर्ती, प्रोफेसर ताकेनोरी होरिमोटो, श्री अंबरीश दासगुप्ता, प्रोफेसर मिलन कुमार सान्याल, श्री ताकुमा ओताकी, प्रोफेसर अजिताव रायचौधरी, प्रोफेसर मकोतो कोजिमा, श्री सिद्धार्थ देशमुख, श्री कोजी सातो, प्रोफेसर गीता ए. कीनी, श्री हाजिमे तानिगुची, प्रोफेसर एस.के. मोहंती, श्री रथेंद्र रमन, श्री सो उमेजाकी, प्रोफेसर लाउ सिम–यी, श्री ताकाशी सुजुकी, डॉ. राजीव सिंह, राजदूत शाहिदुल हक, श्री सुभोदीप घोष सहित अनेक प्रतिष्ठित विद्व ानों तथा भारत, जापान और बांग्लादेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन के दोनों दिन 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और यह आरआईएस के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न आयोजनों का भाग था।

लोगों के बीच परस्पर सहयोग को मजबूत कर रहा है ब्रिक्स सिविल फोरम

ब्रिक्स विशेषज्ञ परिषद–रूस की प्रमुख और एचएसई यूनिवर्सिटी की वाइस रेक्टर डॉ. विक्टोरिया पनोवा के नेतृत्व में रूसी संघ का एक प्रमुख अकादमिक/सिविल सोसायटी प्रतिनिधिमंडल, डब्ल्यू–20 रूसी शेरपा और एचएसई यूनिवर्सिटी के सदस्यों ने 21 फरवरी, 2024 को आरआईएस का दौरा किया। विदेश मंत्रालय ने 2024 में आरआईएस को ब्रिक्स सिविल फोरम के लिए केंद्रीय संस्थान के रूप में नामित किया है। इस अवसर पर, आरआईएस, फोरम फॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) और एचएसई यूनिवर्सिटी, रूस ने संयुक्त रूप से विशेष ब्रिक्स सिविल फोरम गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें निम्नलिखित रूसी प्रतिनिधियों ने भाग लियाः डॉ. विक्टोरिया पनोवा, ब्रिक्स विशेषज्ञ परिषद–रूस की प्रमुख और एचएसई यूनिवर्सिटी की वाइस रेक्टर; डब्ल्यू–20 रूसी शेरपा; श्री दानियाल शचरबन, वाइस रेक्टर के सलाहकार, एचएसई यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर अर्तोम लुकिन, स्कूल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टडीज, फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर फॉर रिसर्च; सुश्री केन्सिया शेवत्सोवा, प्रमुख, इंटरनेशनल पार्टनर्शिप्स ऑफिस, एचएसई यूनिवर्सिटी; और सुश्री वलेरिया गोर्बाचेवा, प्रमुख, मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, एचएसई यूनिवर्सिटी।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित किया, जिसमें पांच नए सदस्यों के शामिल हो जाने से कुल संख्या दस हो चुकी है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत सरकार ने आरआईएस को ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क में वित्त के संबंध में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है, जो समान मुद्रा तंत्र, फिनटेक, जस्ट ट्रांजिशन फाइनेंसिंग और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। डॉ. विक्टोरिया पैनोवा ने रूसी अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क (बीटीटीसी) और ब्रिक्स सिविल फोरम की संरचना और तौर–तरीकों की जानकारी दी। प्रोफेसर अनुराधा एम. चेनॉय, पूर्व प्रोफेसर जेएनयू और सदस्य एफआईडीसी, ने विशेष रूप से बहुपक्षवाद के संदर्भ में ब्रिक्स के बढ़ते महत्व पर गौर किया।

इंटरैक्टिव सत्र में भाग ले रहा प्रतिनिधिमंडल

रूस में पूर्व राजदूत और नैटस्ट्रैट के संयोजक राजदूत पंकज सरन ने वित्तीय संसाधनों और उन्नत प्रौद्योगिकी दोनों की आवश्यकता पर बल देते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के निदेशक राजदूत अशोक के. कांथा ने विशेषकर पांच नए सदस्यों को शामिल करने के साथ पिछले शिखर सम्मेलन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, जेएनयू और सदस्य एफआईडीसी ने वैश्विक आर्थिक प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त की और ब्रिक्स के और अधिक विस्तार के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी। प्रोफेसर अर्तोम लुकिन, स्कूल ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल स्टडीज, फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर फॉर रिसच ने ब्रिक्स की सफलता के लिए भारत, रूस और चीन के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। डीएसटी के पूर्व सलाहकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रमुख डॉ. एस.के. वार्ष्णेय ने सिविल फोरम से प्रौद्योगिकी के सामाजिक निहितार्थों का आकलन करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिपरकता पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने समापन भाषण में पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली के महत्व और प्रौद्योगिकी, विशेषकर एआई के संबंध में नीतिपरकता पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ब्रिक्स के लिए एक सुसंगत धारणा को परिभाषित करने तथा भारत, रूस, अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ त्रिकोणीय सहयोग के माध्यम से सहयोग की संभावनाएं तलाशने की आवश्यकता पर बल दिया।

आरआईएस–आईएफपीआरआई क्षमता निर्माण

बिम्सटेक क्षेत्रीय कृषि व्यापार विश्लेषण

आरआईएस, ने युवा शोधकर्ताओं और नीति विश्लेषकों को कृषि व्यापार के क्षेत्रों से अवगत कराने के लिए डॉ. बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (बीएएसई) यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) वाशिंगटन और फीड द फ्यूचर इनोवेशन लैब फॉर फूड सिक्योरिटी, पॉलिसी रिसर्च, केपिसिटी एंड इंफ्लूएंस (पीआरसीआई)के सहयोग 19–20 फरवरी 2024 तक बीएएसई यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में दो दिवसीय क्षमता–निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बिम्सटेक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत, नेपाल और श्रीलंका के 30 विद्वानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय कृषि क्षेत्रों की समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

(बाएं से) प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी; प्रोफेसर सुरेश बाबू; और प्रोफेसर एस.के.मोहंती

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बिम्सटेक क्षेत्र में कृषि के महत्व को रेखांकित किया और कृषि–औद्योगिक विकास के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापार के परिप्रेक्ष्य से कृषि–मूल्य श्रृंखलाओं का विश्लेषण करने के लिए नई कार्यपद्धतियां विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया। प्रोफेसर एन.आर.भानुमूर्ति, कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर कृषि व्यापार के प्रभाव का विश्लेषण करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। प्रोफेसर सुरेश बाबू, सीनियर रिसर्च फेलो, आईएफपीआरआई ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में चर्चा की और निर्यात–संवर्धित कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिम्सटेक में अंतर–क्षेत्रीय कृषि व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया। बिम्सटेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे ने रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, कृषि परंपराओं और लचीली खाद्य प्रणालियों के लिए टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देते हुए जानकारी प्रदान की।

आईआईएमआर, हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. सी.वी. रत्नावती ने भारत के अनाज निर्यात में खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभाव के बारे में चर्चा की। उन्होंने अनाज की पोषण संबंधी गुणवत्ता, श्रीअन्न के मूल्यवर्धित उत्पादों और खाद्य उत्पादों के निर्यात सुरक्षा मानकों के निर्धारण में एपीडा और एफएसएसएआई जैसे शीर्ष संगठनों की भूमिका पर बल दिया। आईआईएम कलकत्ता के प्रोफेसर पार्थप्रतिम पाल ने कृषि उत्पादों की कवरेज के साथ–साथ कृषि की बहु–कार्यक्षमता और डब्ल्यूटीओ में कृषि पर समझौते पर बहस के बारे में विचार–विमर्श किया। आईजीआईडीआर के प्रोफेसर गणेश कुमार ने कनेक्टिविटी की समस्याओं, व्यापार संबंधी बाधाओं और सुरक्षा मानकों जैसी चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, इनसे निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की पेशकश करते हुए बिम्सटेक देशों में व्यापार के रुझानों के बारे में चर्चा की। पीजेटीएसएयू, हैदराबाद के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर वी प्रवीण राव ने अपने विचार–विमर्श में कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका के बारे में चर्चा की। डिजिटल कृषि 4आईआर प्रौद्योगिकियों के जरिए कृषि–खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को बदलने के प्रति लक्षित इस परिवर्तन की केंद्रीय घटक है, और साथ ही ज्ञान और संसाधनों की दीर्घकालिक सीमाओं को भी तोड़ रही है।

एक पृथक सत्र में, विद्यार्थियों को क्षेत्रीय कृषि व्यापार डेटा से अवगत कराया गया, जहां आरआईएस के प्रोफेसर एस.के. मोहंती और डॉ. पंखुरी गौड़ ने क्षेत्र के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में व्यापार के रुझानों पर चर्चा की।

समापन सत्र में, राजदूत सीएसआर राम, संयुक्त सचिव, बिम्सटेक और सार्क, विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और सिविल सोसायटी, व्यवसायों और युवाओं के माध्यम से लोगों के बीच आपसी संबंधों के महत्व पर जोर दिया। प्रोफेसर एस.के. मोहंती, प्रोफेसर भानुमूर्ति, प्रोफेसर गोपाल नाइक, आईआईएम बैंगलोर और डॉ. पंखुड़ी गौड़ ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और क्षेत्र में कृषि की स्थिति के बारे में अपने अनुभव साझा किए।

त्रिकोणीय सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने त्रिकोणीय सहयोग पर 12 से 14 फरवरी 2024 तक एक क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के भीतर इस पद्धति के उभरते महत्व को स्वीकार करने के लिए जारी व्यापक आरआईएस–जीआईजेड अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें शिक्षा जगत, विकास सहयोग व्यवसायी, सिविल सोसायटी और अन्य हितधारकों सहित 9 विविध संस्थानों के 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को त्रिकोणीय सहयोग और कवर किए गए मॉड्यूल : त्रिकोणीय और दक्षिण–दक्षिण सहयोग, भारत का विकास सहयोग और त्रिकोणीय सहयोग की प्रमुख विशेषताओं सहित अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग की वैश्विक संरचना के बारे में एकीकृत और बहुआयामी समझ की ओर उन्मुख करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा, प्रख्यात भारतीय विशेषज्ञों ने त्रिकोणीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए वैश्विक संरचना और विकास सहयोग के क्षेत्र में भारत के विशिष्ट योगदान के बारे बारीकी से जानकारी प्रदान की।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी

पृष्ठ 1 से जारी...

कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को 20 प्रतिशत राजस्व गहरे समुद्र में, लेकिन बंदरगाह के 12 समुद्री मील के भीतर मौजूद जहाजों से माल उतारने से प्राप्त होता है।

चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हासिल की गई प्रगति के बावजूद, भारतीय बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति सरकार के विजन को साकार करने के लिए आवश्यक थ्रूपुट में होने वाली बड़ी वृद्धि को सीमित करती है। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती तो है ही, लेकिन साथ ही व्यवसाय की इस दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रबंधकीय प्रगति करने का अवसर भी है। उन्होंने तेजी से विकसित हो रहे समुद्री परिदृश्य की सभी समस्याओं के समाधान के लिए सीएमईसी द्वारा की गई विशिष्ट व्याख्यान के आयोजन की पहल को सही दिशा में उठाया गया कदम करार देते हुए उसका स्वागत किया।

डॉ विश्वपति त्रिवेदी, पूर्व केंद्रीय सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय और खान मंत्रालय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रोताओं को इस क्षेत्र का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए क्षेत्र के संबंध में अपना ज्ञान साझा किया। उन्होंने कहा, "समुद्री क्षेत्र में इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ–साथ नवाचार, सांख्यिकी और सुरक्षा के कई तत्व शामिल हैं।" डॉ. त्रिवेदी ने बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी मॉडल की कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बंदरगाह क्षेत्र में 95 प्रतिशत निवेश इसी मॉडल के माध्यम से आने वाला है। उन्होंने कहा कि अनुबंधों पर दोबारा बातचीत से परहेज नहीं करना चाहिए। बंदरगाहों के पीपीपी मॉडलों के अन्य क्षेत्रों से भिन्न होने के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि बंदरगाह राष्ट्र के द्वारपाल होने के नाते संप्रभु प्राधिकरण से जुड़े होते हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में लाल सागर संकट के प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया। उन्होंने इंगित किया कि इस संकट ने न सिर्फ भारतीय व्यापार में व्यवधान की दृष्टि से अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, बल्कि इसकी वजह से अनेक देशों में मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि व्यापार की मात्रा में अत्यधिक कमी आ रही है, जिसके मद्देनजर बीमा और पुनर्बीमा की लागत बढ़ गई है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पुनर्बीमा की लागत लगभग दोगुनी हो गई है।

सीएमईसी के समन्वयक श्री सुभोमोय भट्टाचार्जी ने कहा कि व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन अब नियमित रूप से किया जाएगा। उन्होंने वक्ताओं और श्रोताओं का आभार प्रकट किया।

आरआईएस और आईपीए की संयुक्त पहल समुद्री अर्थव्यवस्था व संयोजन केंद्र (सीएमईसी) को जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के समुद्री विजन को आगे बढ़ाने तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के लिए नीतिगत सलाहकार शाखा के रूप में कार्य करने के लिए किया गया। सीएमईसी नियमित रूप से न्यूजलैटर, प्रमुख समसामयिक मुद्दों पर कॉमेंट्री प्रकाशित करता है और नीतिगत सारांश, शोध लेखों आदि के रूप में नीतिगत विमर्श में योगदान देता है।

पृष्ठ 9 से जारी...

में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, वांछित गुणों वाले विभिन्न जीनोम संपादित अनाज, दालें, तिलहन और फलों की किस्में विकसित की जा रही हैं। फसलों की इस प्रक्रिया में चावल, सरसों, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, हरा चना, गेहूं, गन्ना, आम, केला और टमाटर शामिल हैं। उन्होंने जलवायु–स्मार्ट कृषि के लिए अत्यधिक कुशल जीनोम–संपादन तकनीक सीआरआईएसपीआर की प्रासंगिकता को भी रेखांकित किया। अंत में, प्रोफेसर बंसल ने जोर देकर कहा कि जीनोम संपादन जैसे विज्ञान–आधारित नवाचार हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करते हुए किसानों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से होने वाले नुकसान से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सशक्त बनाएंगे।

पृष्ठ 12 से जारी...

उन्होंने लाइफ पर एलपी द्वारा हल की गई मांग–पक्ष से संबंधित चुनौतियों की पड़ताल की और मानव विकास के बीच अंतरसंबंधों को रेखांकित किया, जो सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पॉवरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी (सीईईपी–यानी स्थिरता, समानता, सशक्तिकरण और उत्पादकता) के 4 स्तंभों और लाइफ परिप्रेक्ष्य पर आधारित हैं। प्रोफेसर पम्मी दुआ, प्रोफेसर एवं निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सामुदायिक सहभागिता के साथ समग्र स्थिरता के अंतर्संबंधों पर जोर देते हुए बाहरी आयामों (पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक) और आंतरिक आयामों (मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोण) दोनों पर विचार करते हुए समग्र स्थिरता के बारे में चर्चा की। प्रोफेसर दनांग परिकेसिट, प्रोफेसर, इंजीनियरिंग अर्थशास्त्र और परिवहन नीति; संस्थापक और वरिष्ठ शोधकर्ता, द सेंटर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स स्टडीज, यूनिवर्सिटास गदजाह माडा, इंडोनेशिया, ने इंडोनेशिया के जी–20 प्रयासों पर विशेष ध्यान देते हुए, ग्लोबल साउथ के लिए समावेशी वित्त को बढ़ावा देने, ढांचागत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए हरित बांड की वकालत की।

आरआईएस ने 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं : ग्लोबल साउथ में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना' विषय पर एक पूर्ण सत्र भी आयोजित किया। इस सत्र में प्रोफेसर फुकुनारी किमुरा, प्रोफेसर मुस्तफिजुर रहमान, डॉ. निहाल पिटिगाला, डॉ. गणेशन विग्नाराजा और प्रोफेसर एस के मोहंती जैसे प्रमुख वक्ताओं ने भाग लिया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. रजत नाग ने की। सत्र में इस बारे में चर्चा की गई कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) ने विकासशील देशों के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, विकासशील देशों के संदर्भ में जीवीसी में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अधिकांश लाभ विकसित देशों द्वारा हासिल किए जाते हैं। इससे मूल्य श्रृंखलाओं के विभिन्न हितधारकों के बीच लाभ के न्यायसंगत वितरण का महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। इसलिए, व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण बनाए रखने और जीवीसी के माध्यम से टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जीवीसी का गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ में जीवीसी के बढ़ते दायरे के लिए क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की गई। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करने में प्रौद्योगिकी और व्यापार वित्त, सेवा व्यापार, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण कारक हैं। दक्षिण–दक्षिण सहयोग उत्पादन और व्यापार में दक्षता बढ़ाने के लिए जीवीसी के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन दे सकता है।

दूसरे दिन रात्रि भोज के दौरान प्रोफेसर फुकुनारी किमुरा ने वैश्वीकरण या विकास पर विशेष संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्वीकरण समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के अनेक देशों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पृथक्करण (या अनबंडलिंग) का पहले (उद्योग–दर–उद्योग श्रम का विभाजन) और दूसरे (कार्य–दर–कार्य श्रम का विभाजन) का लाभ उठाया है। अनेक विकासशील देश अब भी वैश्वीकरण के रुझान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति का लाभ उठाते हुए मूल्य श्रृंखलाओं के तीसरे पृथक्करण (व्यक्ति–दर–व्यक्ति श्रम का विभाजन) में भाग ले सकते हैं और खुद को संलग्न कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्क्लेव के आखिरी दिन आरआईएस ने दक्षिण एशिया में प्रांतीय और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं पर एक गोलमेज सत्र का भी आयोजन किया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर नागेश कुमार ने जबकि सह–अध्यक्षता प्रोफेसर एस के मोहंती ने की। सत्र में डॉ. पोष राज पांडे, डॉ. एलेक्सी क्रावचेंको, डॉ. उपलट कोरवातनसाकुल, डॉ. मनोज थिब्बोतुवावा, डॉ. लोडे फुंटशो और प्रोफेसर प्रबीर डे जैसे विशेषज्ञों ने विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और दक्षिण एशिया में मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने में आईसीटी की भूमिका से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की। प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि दक्षिण एशिया वैश्विक मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया में देर से आया है और इसकी आर्थिक क्षमता का समुचित उपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान में, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं प्राथमिक और निम्न–प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं। ये मूल उपायों के सख्त नियमों के साथ उच्च टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाओं के अधीन हैं, जो गहन क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में बाधा का कार्य करते हैं। हालांकि, यह क्षेत्र वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जो क्षेत्र के भीतर गहन आर्थिक एकीकरण को उत्प्रेरित कर सकता है। कोविड–19 के बाद उत्पादन नेटवर्क का वैश्विक स्तर पर पुनः अभिविन्यास चीन से परे रखे जाने को रेखांकित करते हुए सत्र में दक्षिण एशिया के एक नए आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में विकसित होने के सामर्थ्य का पता लगाया गया। मजबूत और लचीली क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए क्षेत्र में कृषि, परिधान, प्रीमियम व्यापार, विनिर्माण क्षेत्र और विशेष रूप से आईसीटी जैसी मूल्य श्रृंखला से संबंधित सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- सेंटर फॉर स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईआर) और डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसओएसएस–इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा संयुक्त रूप से 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 'जी–20 की अध्यक्षता और भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जी–20, भारत और ग्लोबल साउथ पर सत्र में पैनलिस्ट।
- काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग (सीआईईयू) द्वारा 12–13 जनवरी 2024, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2024 में "ग्लोबल साउथ का एजेंडा: बहुपक्षीय विकास बैंकों का भविष्य" और "हॉट डिबेट: केस फॉर डिगवर्नमेंटाइजेशन ऑफ बैंक्स ओर नॉट" विषय पर दो सत्रों का संचालन किया और "भारत फर्स्ट: भारत और वैश्विक वित्तीय संरचना" पर सत्र में पैनलिस्ट।
- विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा 17 जनवरी 2024, को नई दिल्ली में जी–20 शेरपा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लाइफ अर्थव्यवस्था और जीएएलईआरआई पहल पर प्रस्तुति दी।
- ब्लिट्ज़ इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 24 जनवरी 2024 को ब्रिजिंग माइंड्स, शेपिंग फ्यूचर्स विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।
- आईआईएम विशाखापत्तनम, क्षमता निर्माण आयोग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा 29 जनवरी 2024 को संयुक्त रूप से आयोजित युवा वैज्ञानिक प्रेरण कार्यक्रम में 'सामाजिक आर्थिक वातावरण और विकास की अनिवार्यता' पर प्रस्तुति दी।
- कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर (सीएडब्ल्यू), सिकंदराबाद द्वारा 2 फरवरी 2024 को हायर एयर कमांड कोर्स (एचएसीसी) में 'सेना के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन' पर आयोजित कैप्सूल में 'आर्थिक सुरक्षा' पर प्रस्तुति दी ।
- यूनेस्को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, स्लोवेनिया द्वारा संयुक्त रूप से 5–6 फरवरी 2024 को स्लोवेनिया में आयोजित 'ग्लोबल फोरम ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : चेंजिंग लैंडस्कैप ऑफ एआई गवर्नेंस' में "एसटीआई और सामाजिक–आर्थिक विकास: भारतीय अनुभव" पर प्रस्तुति दी। जोज़ेफ़ स्टीफन इंस्टीट्यूट द्वारा 6 फरवरी 2024 को स्लोवेनिया में आयोजित पहले स्लोवेनियाई–भारतीय विज्ञान और नवाचार दिवस में "भारत और स्लोवेनिया के साथ एसटीआई सहयोग" पर मुख्य भाषण भी दिया।
- द साउथ ईस्ट एशियन बैंक्स (एसईएसीईएन) रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 15 फरवरी 2024 को मुंबई में 'आर्थिक बाधाएं मिटाना और वित्तीय समावेशन आगे बढ़ाना : परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां' विषय पर आयोजित 59वें एसईएसीईएन गवर्नर्स सम्मेलन में 'मुद्रास्फीति के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरक और मार्ग– आगे की चुनौतियां'' विषय पर गवर्नर्स पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में 'एआई और नैतिकता : उद्योग और शिक्षा जगत के परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में 'शिक्षा में एआई और नैतिकता: नवाचार और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संतुलित करना' पर एक सत्र का संचालन किया।
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), आईआईटी, मद्रास और विज्ञान भारती द्वारा 29 फरवरी 2024 को चेन्नई में संयुक्त रूप से आयोजित तीसरी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस में 'नीली अर्थव्यवस्था में महासागरों का सतत उपयोग' पर पूर्ण वार्ता में पैनलिस्ट।
- सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएसएस) द्वारा 1 मार्च 2024 को हैदराबाद में आयोजित 'प्रौद्योगिकी के साथ न्यायसंगत विकास परिवर्तन: ग्लोबल साउथ के लिए भारतीय अनुभव की प्रासंगिकता' विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान दिया।
- क्षमता निर्माण आयोग द्वारा 6 मार्च 2024 को आयोजित कार्यक्रम में 'विज्ञान कूटनीति: मुद्दे, नीतिगत विकल्प और दक्षिणी परिप्रेक्ष्य' पर प्रस्तुति दी।
- आईसीआरआईईआर द्वारा 26 मार्च 2023 को नई दिल्ली में 'जी–20 और जी–7 को निकट लाने में भारतीय और जापानी अध्यक्षताओं की भूमिका' विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट।

प्रोफेसर एस के मोहंती

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को कृषि उत्पादों पर अध्ययन के संबंध में आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो–पैसिफिक स्टडीज (आईसीआईपीएस), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को "हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भू–रणनीतिक, भू–आर्थिक और भू–राजनीतिक घटनाक्रम" विषय पर आयोजित दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित अतिथि।
- डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच और पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑन इफेक्टिव ट्राइंगुलर कोऑपरेशन (जीपीआई) के सहयोग से 2 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइएंगुलर कोऑपरेशन (एसीटीआरसी) में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और 'त्रिकोणीय सहयोग –वैश्विक लक्ष्यों के प्रति साझेदारीपूर्ण दृष्टिकोण' पर चर्चा की।
- नीति आयोग द्वारा 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 'प्रगति और समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार' पर आयोजित जी–20 थिंक टैंक कार्यशाला में भाग लिया और जी–20 अध्यक्षताओं में जीवीसी पर वैश्विक व्यापार चर्चा में जीवीसी की गतिशीलता पर प्रस्तुति दी।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में सचिव, एमओसीआई के साथ भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- इंडिया फाउंडेशन द्वारा 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फाउंडेशन–फुडन यूनिवर्सिटी द्विपक्षीय सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया और व्यापार असंतुलन का प्रबंधन और जनता के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाना–सत्र में भारत चीन व्यापार संबंधों पर प्रस्तुति दी।
- 15वें दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023–दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना'' में बतौर वक्ता भाग लिया और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (एमपी–आईडीएसए), नई दिल्ली द्वारा 14 दिसंबर 2023–12–15 को आयोजित सत्र–दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना में 'दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय पहचान की जद्दोजहद की संभावनाएं तलाशना' पर प्रस्तुति दी।
- प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 20 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में 'भारत का मुक्त व्यापार समझौता और समग्रीकरण समझौता पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 106वें वार्षिक सम्मेलन–2023 में वक्ता और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 22 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के मुद्दों और नए क्षेत्रवाद के साथ इसके प्रयोग पर विशेष पैनल में प्रस्तुति दी।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा रेड सैंडर्स पर आयोजित की गई विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया और चेन्नई में 5 जनवरी 2024 को आईटीसी एचएस कोड और रेड सैंडर्स के व्यापार और भारत में निर्यात पर इसके प्रभावों पर प्रस्तुति दी।
- विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2024 को 'भारत मंडपम' नई दिल्ली में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड (बीओटी) की बैठक में भाग लिया।
- ओशन मॉडलिंग, एप्लाइड रिसर्च एंड सर्विसेज (ओ–एमएआरएस), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में संयुक्त रूप से आयोजित इंडियन ओशन रीजनल डीकेड कॉन्फ्रेंस 2024: ब्रिजिंग बिलियन्स टू बार्सिलोना में 2 फरवरी 2024 को भाग लिया और विज़न 2030: व्हाइट पेपर ऑफ द चैलेंज पर प्रस्तुति दी।
- फीड द फ्यूचर इनोवेशन लैब फॉर फूड सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्च, कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस (पीआरसीआई), मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट(यूएसएआईडी) द्वारा आईएफपीआरआई पीआरसीआई परियोजना के तहत वाशिंगटन डीसी अमेरिका में 6–8 मार्च 2024 को आयोजित दूसरे पीआरसीआई सम्मेलन के समापन पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

नवीनतम प्रकाशन

डॉ. भास्कर बालकृष्णन और डॉ. राम उपेन्द्र दास को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि

डॉ. भास्कर बालकृष्णन
(25 सितम्बर 1947–21 जनवरी 2024)

डॉ. राम उपेन्द्र दास
(18 नवंबर 1967 – 25 फरवरी 2024)

पुस्तकें/रिपोर्ट्स

साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (एसटीआई) फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल्ज (एसडीजी) रोडमैप्स, आरआईएस, नई दिल्ली 2024

एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वैल्यू एडिशन इन बिम्सटेक रीजन, आरआईएस–आईएफपीआरआई, नई दिल्ली, 2024

आरआईएस चर्चा पत्र

#292: ट्रेड एंड एनवायरनमेंट : ट्रैकिंग एनवायरनमेंटल प्रोविजन्स इन रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स (आरटीए) टू मेक एप्रोप्रिएट इंडियन स्टैन्स, द्वारा अंशुमन गुप्ता

#291: इंडियाज जी–20 प्रेसिडेंसी ऐज अ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, द्वारा सुशील कुमार

#290: एनालाइजिंग इंडिया–नेपाल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन : स्टेटस, चैलेंजिस एंड वे फॉरवर्ड, द्वारा पंकज वशिष्ट

#289: एसडीजी गैप्स एंड टेक्नोलॉजी नीड्स इन डेवेलपिंग कंट्रीज : स्कोप फॉर लोकली एजाइल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स, द्वारा सब्यसाची साहा

#288: स्ट्रेंगथनिंग रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया: अ स्ट्रेटेजी पेपर ऑन रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, द्वारा प्रबीर डे

एआईसी कॉमेंट्रीज

- संख्या 48: इंडिया–आसियान रिलेशन्स : नीड फॉर डीपर एंगेजमेंट द्वारा चिंतामणि महापात्र
- संख्या 47: एड्रेसिंग नॉन–ट्रेडिशनल मैरीटाइम थ्रेट्स–ऑप्शन्स फॉर इंडिया एंड आसियान द्वारा कैप्टन सरबजीत एस परमार
- संख्या 46: फोस्टरिंग फ्यूचर आसियान इंडिया कोलेब्रेशन : अ स्ट्रेटेजिक फाइव–प्रॉन्गड एजेंडा, द्वारा पियानत सोइखम

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

बालकृष्णन, भास्कर. 2024. "मैनेजमेंट ऑफ ओशन स्पेस अराउंड इंडिया एंड द हाई सीज़ ट्रीटी, आईसीडब्ल्यूए, जनवरी।

चतुर्वेदी,एस. (28 जनवरी, 2024). "द क्रूशियल रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन नेशन–बिल्डिंग" ब्लिटज़िंडियम। https://blitzindiamedia.com/the-crucial-role-of-highereducation-in-nation-building/

चतुर्वेदी, एस. 2023. "लाइफ, ग्लोबल गवर्नेंस एंड क्लाइमेट चेंज: प्रिंसिपल–बेस्ड एक्शन एजेंडा फॉर जी–20". इकबाल सिंह सेविया एट. अल. (संपा.) इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ जी–20 : शेपिंग पॉलिसीज फॉर अ बैटर वर्ल्ड में, ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग।

डे, पी. 2024. "शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक नैरेटिव्स: 40 ईयर्स ऑफ आरआईएस" हिंदुस्तान टाइम्स, 5 जनवरी। डे, पी. और दुरईराज, के. 2024. "असेसिंग द ट्रेड–कनेक्टिविटी लिंकेजिज इन साउथ एशिया इन पोस्ट पैंडेमिक पीरियड: ऐन इम्पीरिकल इन्वेस्टिगेशन" जर्नल ऑफ एशिया–पैसिफिक इकोनॉमी, 29 (2)।

मोहंती, एस.के. 2024. प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डायनेमिज्म इन साउथ एशिया : ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऐज ड्राइवर्स ऑफ रीजनल डेवेलपमेंट। द रूटलेज हैंडबुक ऑफ साउथ एशिया (पृ.सं. 176–197) में। रूटलेज इंडिया.

मोहंती, एस.के. 2024. 'प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्ल्यू इकोनॉमी इन इंडिया : इमर्जिंग पॉलिसी चैलेंजेज एंड द वे फॉरवर्ड', करंट साइंस, 26 (2)।

RIS
Research and Information System for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ईमेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: www.ris.org.in

हमें यहां फॉलो करें:

www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबन्ध सम्पादक : तीश मल्होत्रा